भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

17.12.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2768 का उत्तर

रेलवे का व्यय

2768. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
श्रीमती भारती पारधी:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय रेलवे के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सुरक्षा कार्यों और रेलपथ नवीनीकरण के लिए निर्धारित धनराशि का पूर्ण उपयोग किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो धनराशि का कम उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जोन-वार मुद्रीकरण के लिए चिन्हित कुल रेलवे भूमि कितनी है और भूमि मुद्रीकरण से प्राप्त राजस्व कितना है;

(घ) क्या राज्य सरकार की अनुमति या स्थानीय निकाय के अनुमोदन से संबंधित मुद्दों के कारण कोई भूमि मुद्रीकरण परियोजनाएँ लंबित हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वित्तीय स्थिरता संबंधी लक्ष्यों के अनुरूप गैर-भाड़ा राजस्व बढ़ाने और पूंजीगत परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता पर निर्भरता कम करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): भारतीय रेल की आय और व्यय का ब्यौरा वर्ष 2022-23 से निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

	2022-23	2023-24	2024-25
कुल राजस्व	2,40,177	2,56,094	2,65,678
कुल व्यय	2,37,660	2,52,834	2,63,018
अधिशेष (निवल राजस्व)	2,517	3,260	2,660
कुल पूंजीगत व्यय (बजट स्रोत)	1,62,658	2,45,592	2,54,312

रेलवे-वार कुल आय और व्यय का ब्यौरा भारतीय रेल के वार्षिक सांख्यिकीय विवरण में उपलब्ध है, जो भारतीय रेल की वेबसाइट (https://indianrailways.gov.in) पर उपलब्ध है।

वर्ष 2025-26 के दौरान, संरक्षा संबंधित गतिविधियों के लिए 1,16,514 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें रेलपथ नवीनीकरण और रेलपथ रखरखाव की गतिविधियाँ शामिल हैं। नवंबर, 2025 तक इसका उपयोग लगभग 70% है।

(ग) और (घ): रेलवे की तात्कालिक परिचालन आवश्यकताओं हेतु आवश्यक न होने वाली खाली भूमि को वाणिज्यिक विकास हेतु रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को सौंपी गई है। आरएलडीए को लगभग 1308 हेक्टेयर भूमि मुद्रीकरण हेतु सौंपी गई है। पिछले तीन वर्षों में भूमि एवं स्थानों के वाणिज्यिक उपयोग से भारतीय रेल द्वारा अर्जित राजस्व 8,209 करोड़ रुपए रहा है।

भूमि मुद्रीकरण परियोजनाओं का निष्पादन कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि उचित भूमि दस्तावेजों की उपलब्धता, भूमि उपयोग में परिवर्तन, योजनाओं की स्वीकृति और कानूनी कार्रवाई आदि, जो पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं।

(ङ): भारतीय रेल ने विज्ञापन और अन्य नवीन विचारों के माध्यम से गैर-भाड़ा राजस्व बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे:

- स्टेशनों पर रेल डिस्प्ले नेटवर्क (आरडीएन) के माध्यम से विज्ञापन।
- आउट ऑफ होम (ओओएच) के माध्यम से विज्ञापन
- चल परिसंपत्तियों जैसे सवारीडिब्बों और गाड़ी के अंदर विज्ञापन।
- यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नवोन्मेषी समाधान जैसे कि स्लीपिंग पॉड्स की सुविधा, सिंगल ब्रांड प्रीमियम आउटलेट, ऑटो और टैक्सी बुकिंग की सुविधा के लिए कियोस्क, भुगतान के आधार पर ई-व्हीलचेयर सुविधा, हेल्थ कियोस्क, जेनेरिक दवाइयाँ बेचने के लिए मेडिकल स्टोर।
- पार्किंग अनुबंधों से लाइसेंस शुल्क
- भूमि का मुद्रीकरण
- खानपान अनुबंधों से प्राप्तियां

समग्र राजस्व बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं

- नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए, नई लाइनों का निर्माण, मौजूदा लाइनों का बहु-पथन और मौजूदा लाइनों का आमान परिवर्तन करके बड़े पैमाने पर रेल नेटवर्क का विस्तार कार्य शुरू किया गया है। 11 वर्षों के दौरान बिछाई गई नई पटरियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ
2009-14	7,599 कि.मी.
2014-25	34,428 कि.मी.

इसके अलावा, 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, 431 परियोजनाएं (154 नई लाइन, 33 आमान परिवर्तन और 244 दोहरीकरण) स्वीकृत की गई हैं। इसका सारांश निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी.)	मार्च, 2025 तक पूरी की गई लंबाई (कि.मी.)	शेष लंबाई (कि.मी.)	लागत (करोड़ रु. में)
नई लाइन	154	16,142	3,036	13,105	3,77,389
आमान परिवर्तन	33	4,180	2,997	1,183	43,820
दोहरीकरण/ मल्टीट्रैकिंग	244	15,644	6,736	8,909	2,53,711
कुल	431	35,966	12,769	23,197	6,74,920

- यार्ड का पुनर्निर्माण, बाइपास/कॉर्ड लाइन का निर्माण, रेल फ्लाईओवर आदि के द्वारा परिचालन संबंधी बाधाओं को दूर करना।

- लुधियाना से सोननगर (1337 कि.मी.) तक पूर्वी समर्पित माल गलियारा (ईडीएफसी) और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (जेएनपीटी) से दादरी (1506 कि.मी.) तक पश्चिमी समर्पित माल गलियारा (डब्ल्यूडीएफसी) का निर्माण शुरू किया जा चुका है। कुल 2843 कि.मी. में से 2741 मार्ग कि.मी. (96.4%) को कमीशन किया जा चुका है और परिचालित किया जा रहा है।

- भारतीय रेल ने रेल लाइनों के विद्युतीकरण कार्य को मिशन मोड में शुरू किया है। अब तक लगभग 99.1% बड़ी लाइन नेटवर्क को विद्युतीकृत किया जा चुका है। वर्ष 2014 के पहले और बाद के विद्युतीकरण कार्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	मार्ग किलोमीटर
2014 से पूर्व	21,801
2014-25	46,900

- **माल डिब्बों और इंजनों का प्रापण: माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने के लिए, भारतीय रेल के माल डिब्बों का बड़ी संख्या में प्रापण किया गया है और इंजनों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2014 से 2025 के दौरान, लगभग 2 लाख माल डिब्बों का प्रापण किया गया और माल लदान तथा गतिशीलता बढ़ाने के लिए 10,000 से अधिक इंजन शामिल किए गए हैं।**

- **सामान्य प्रयोजन के माल डिब्बों, विशेष प्रयोजन/उच्च क्षमता वाले माल डिब्बे सीमेंट, तेल, स्टील, फ्लाई-एश, ऑटोमोबाइल आदि के लिए ऑटोमोबाइल वाहक माल डिब्बों में निवेश में उद्योग की भागीदारी। अब तक, लगभग 240 विशेष प्रयोजन वाले माल डिब्बों के रेक, 374 सामान्य प्रयोजन वाले माल डिब्बों के रेक और 48 ऑटोमोबाइल माल डिब्बों के रेक शामिल किए गए हैं।**

- **'गति शक्ति मल्टी-मोडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी)' नीति के अंतर्गत अब तक 118 नए जीसीटी कमीशन किए गए हैं, जिनकी अनुमानित यातायात क्षमता 192 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2023-24 से माल और पार्सल टर्मिनलों के सुधार के लिए 14,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।**

- **रेलवे सुधारों के तहत थोक सीमेंट परिवहन को सुगम बनाने के लिए हाल ही में रेल भूमि पर टर्मिनल स्थापित करने के लिए "थोक सीमेंट टर्मिनल नीति" शुरू की गई है।**

- **मांग के अनुसार रेक/माल डिब्बों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।**

- **माल यातायात परिचालन में सुचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर के परिसंपत्तियों की निगरानी एवं उपयोगिता में सुधार।**

- **उच्च अश्वशक्ति वाले इंजनों को शामिल करना।**

- **माल डिब्बों और इंजनों की अनुरक्षण पद्धतियों में सुधार के परिणामस्वरूप यातायात उपयोग के लिए इंजनों और चल स्टॉक की बढ़ी हुई उपलब्धता।**

- **अधिक यातायात के परिवहन के लिए रेलपथ और सिगनल प्रणाली के मानकों में सुधार।**
- **कर्मचारियों और अधिकारियों को नई प्रौद्योगिकी और प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रशिक्षण देना।**

*****